(क) देश में वनस्पति तेलों तथा सरसों के तेल की कितनी आवश्यकता है और गत वर्ष इसका वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या कमी का कारण कम उत्पादन है अथवा इन मदों का निर्यात है ;

(ग) इस वर्ष इन तेलों का कितना उत्पादन हुआ और क्या यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी होगी अथवा हमें इनका आयात करना पड़ेगा; और

(घ) इन तेलों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) नवम्बर, 1975--अक्तूबर, 1976 तक के तेल वर्ष के लिए वनस्पति तेलों, जिनमें सरसों का तेल भी शामिल है, की मांग का अनुमान लगभग 32 लाख मीटरी टन लगाया गया था । इसका उत्पादन 29.44 लाख मीटरी टन हुआ, जिसमें 6.1 लाख मीटरी टन सरसों का तेल था ।

(ख)कमी का कारण तेलों का कम उत्पादन था ।

(ग) नवम्बर, 1976--अक्टूबर, 1977 तक के तेल वर्ष में लगभग 23.6 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है । यह कमी जिसमें वनस्पति उत्पादन के निवेशों का प्रमुख भाग शामिल है, आयात से पूरी की जा रही है ।

(घ) तिलहनों का देसी उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य तथा अल्पकालीन उपाय किये जा रहे हैं ।

Branches of Nationalised Banks in Orissa

4449. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the number and location of branches of nationalised banks working in Orissa;

(b) the nature of credit facilities being afforded by them; and

(c) number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes who have given credit facilities and other assistance by these banks so far?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Public sector banks had 422 branches functioning in Orissa as at the end of April 1977. Of these 219 branches were located at rural centres, 120 were located at semi-urban centres, 79 were located at urban centres and 4 branches were located at port-towns

(b) Commercial banks, including public sector banks, meet the credit requirements of the productive sectors of economy such as agriculture, industry and trade etc. Rural and semi-urban branches of the public sector banks, in particular, extend credit assistance to neglected sectors such as Agriculture and allied activities, Small Scale Industry, Small Road and Water Transport, Retail Trade and Small Business and Professional and Self-employed persons.

(c) Banks do not maintain communitywise classified data regarding their loan disbursements.

Concession in the rate of Interest for Agriculture

4450. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of FINANCE